# Hica an Usiya The Gazette of India

## धनावारण EXTRAORDINARY

भाग II-- सण्ड 3-- उपलब्द (1)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

त्राविहार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 12]

नई विल्ली, ज्ञनिवार, जनवरी 19, 1974/वीब 29, 1885

No. 12]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19, 1974/PAUSA 29, 1895

इस भाग में भिग्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रसम संकलन के इस में रेखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

#### ORDER

New Delhi, the 19th January 1974

THE NORTH-EASTERN AREAS (REORGANISATION)
(ARUNACHAL PRADESH) ADAPTATION OF LAWS
(No. 3) ORDER, 1974

G.S.R. 17(E).—Whereas by section 79 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the Central Government is empowered, by Order, to make such adaptations and modifications in any law relating to a matter in List II or List III in the Seventh Schedule to the Constitution, as may be necessary or expedient for the number of facilitating the application of such law in relation to the Union territory of Arunachal Pradesh:

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the raid section 79, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the North-Eastern Areas (Leorganisation) (Arunachal Fradech) Adaptation of Laws (No. 3) Order, 1974.

- (2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of January, 1972.
  - 2. (1) In this Order.—
    - (a) "appointed day" means the 21st day of January, 1972;
    - (b) "existing law" means any State Act or Provincial Act or any Regulation made under the Government of India Act, 1870, or under the Government of India Act, 1935, and in force immediately before the appointed day in the whole or any part of the territories now comprised in the Union territory of Arunachal Pradesh and includes any rule, order, bye-law, scheme, notification or other instrument made under such Act or Regulation, but does not include any law relating to a matter enumerated in the Union List;
    - (c) "law" has the same meaning as in clause (g) of section 2 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971.
- (2) The General Clauses Act, 1897, applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
- 3. As from the appointed day, the Act and the Regulation mentioned in the Schedule to this Order shall, until altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule.
- 4. (1) Whenever an expression mentioned in column 1 of the Table hereunder printed occurs (otherwise than in a title or preamble or in a citation or description of an enactment) in an existing law, whether such law is mentioned in the Schedule to this Order or not, then, in the application of that law to the Union territory of Arunachal Pradesh, or, as the case may be, to any part thereof, unless that expression is by this Order expressly directed to be otherwise adapted or modified, or unless the context otherwise requires, there shall be substituted therefor the expression set opposite to it in column 2 of the said Table, and there shall also be made in any sentence in which that expression occurs, such consequential amendments as the rules of grammar may require.

#### TABLE

	·	•		. } Union territory of Arunachai Pradesh
				Gauhati High Court (the High Court of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura)
•	•			
				. Arunachal Pradesh Gazette
	:			

- (2) In any existing law, references to-
  - (i) the State Government of Assam,
  - (ii) the Government of Assam,
  - (iii) the Government,
  - (iv) the Governor of Assam, or
  - (v) the Governor,

shall, save as otherwise expressly provided in any other Law for the time being in force, be construed as references to the Central Government and, unless otherwise directed by the Central Government, as including references to the Administrator of the Union territory of Arunachal Pradesh appointed by the President under article 239 of the Constitution.

5. The provisions of this Order which adapt or modify any law so as to alter the manner in which, the authority by which, or the law under, or in accordance with, which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, licence, permission, award. commitment, attachment, bye-law, rule or regulation, duly made or issued, or anything duly done, before the appointed day; and any such notification, order, licence, permission, award, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or thing may be revoked, varied or un-done in like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and under, and in accordance with, the provisions them applicable to such a case.

#### THE SCHEDULE

THE BENGAL PUBLIC DEMANDS RECOVERY ACT, 1913

(BENGAL ACT 3 OF 1913)

Section 5.—In sub-section (1), in the proviso, for "Assam", substitute "Arunachal Pradesh".

# THE ASSAM FOREST REGULATION, 1891

(REGULATION 7 OF 1891)

Section 1.—In sub-section (2), for "the whole of the territories edministered by the Government of Assam", substitute "the whole of the Union territory of Arunachal Pradesh".

[No. F. 19(1)/72-L.I. Vol. IV]

## नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1974

रूबीतर क्षेत्र (रुतर्ग 5त) (प्रवमायन नरेश) विश्वियों का अतुकूलन (सं • 3) आदेश, 1974 सा • का • का • का • का • का विश्व के स्वाद क

अनः श्रत्रः उक्त धारा 79 द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्निलिखित भादेश करती है, भर्कात :——

- (1) इन अदिश का नाम पर्नोत्तार क्षेत्र (गुनर्गठन) (श्रहगाचल प्रदेश) विश्वियो का अनुकूलन (सं०3) आदेश, 1974 है।
  - (2) यह ऋदिश 21 जनवरी, 1972 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
  - 2 (1) इस ग्रादेश में,-

142

- (क) "नियन दिन" से 21 जनवरी, 1972 श्रीमंत्रेत है ;
- (ख) ''तियमान विवि'' से कोई रैसा राज्य अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, 1870 के अधीन या भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन बनाया गया कोई ऐसा विनियम अभिनेत है जा अध्यावल प्रदेश राज्यक्षत्र में अब समाविष्ट समस्त राज्यक्षेत्रों में या उनके किसं। भाग में नियत दिन के ठीक रूर्व राष्ट्र को और इसके अन्तर्गत ऐसे अधिनियम या विनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम, आदेश, उपविधि, स्कीम, अधिमूचना या अन्य लिखिन भी हैं, जिन्तु इसके अन्तर्गत सब सुची में प्राणिन किसी जिथम से संबंधित कोई विधि नहीं है;
- (ग) "विश्वि" का बही प्रयं होगा जो रूर्वोत्तर क्षेत्र (गुनगंठन) मधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (छ) में उसका है।
- (2) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, इन आदिण ने निर्यापन के लिए वैसे की जागू हागा जैने वर जिनो केदोय अधिनियम के निर्यास के लिए लागुहोता है।
- 3 इस प्रदेश की प्रतुन्तों से उल्लिखित प्रिविनियम पीट विकास जब तक कि वे किसी तक्षम प्रिवान मंडत वर प्रथम गतम प्रिविकारी इत्यापिदिवीं है कि पित सा समीवित वर कर दिएं, जाए उत्त प्रतुन्तों द्वारा निविष्ट प्रतुक्तनों स्रीर उपन्तरों के प्रयंत रहते हुए, नियह हिन से प्रवातित्वी दोंगे।
- এ (1) जब लभो इन्हेनीचे मुक्रिन सारणी के स्तम्भ 1 में ? लिखिन पद, (किसी अर्धिनियमित के शीर्षक या उद्देशिका या प्रोह्नरम या वर्णन के अरन्य।) किसी विद्यमान विधि में प्राण,

चाहे ऐसी विधि इस आदेण की अनुसूची में अल्लिखित हो या नहीं, तो यथास्थिति, श्ररुणाचल प्रदेश मंघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को उस विधि के लागू होने में, जब तक कि वह पद, इस आदेश द्वारा अभिव्यक्त का से अन्यथा अनुकूलित या उपान्तरित करने के लिए निदिष्ट न किया गया हो, या जब तक कि संदर्भ से श्रन्यथा अने क्षित न हो, उसके लिए उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में उसके सामने दिया गया पद प्रतिस्थापित किया जाएगा, श्रीर किसी ऐसे वाक्य में जिसमें वह पद श्राए, ऐसे पारिणामिक संशोधन भी किए जाएंगे, जो व्याकरण के नियमों से श्रवेक्षित हों।

## स≀रणी

श्रदगाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र ग्रमम राज्य गोहाटी उच्च न्यायालय (ग्रमम, नागालैण्ड, उच्च न्यायालय मेघालय, मणियुर श्रीर विषुरा उच्च न्यायालय) श्रमम उच्च न्यायालय ग्रमम उच्च न्यायालय श्रहणाचल प्रदेश राजपत्र राजपत्न अद्याचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र राज्य (सिवाय वहां के जहां वह ''राज्य 🚶 सरकार"या असम राज्य"पद में श्राता हो) (2) किसी विद्यमान विधि में, -(i) श्रसम राज्य सरकार, (ii) श्रसम सरकार, (iii) सरकार., (iv) श्रमम का राज्यपाल, या (v) राज्यवाल,

के प्रति निर्देश से, तत्समय प्रवृत्त किसी श्रन्य विधि में श्रिभव्यक्त रूप से श्रन्थथा उपबंधित के सिवाय, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिर्देश है श्रीर इनके श्रन्तर्गत, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रन्थथा निर्दिष्ट न किया जाए, सविधान के श्रनुच्छेद 239 के श्रधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के प्रणासक के प्रति निर्देश भी वें।

5. इस भादेण के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि को ऐसे अनुकूलित या उपान्तिरत करते हो जिससे उस रीति में जिस में, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा, या वह विधि जिसके अधीन या अनुसार, कोई शिक्तयां प्रयोक्तव्य हों, पिवर्तन हो जाए, नियत दिन के पूर्व सम्यक रूप से बनाई गई या जारी की गई किसी अधिसूचना, आदेश, अनुक्राप्ति, अनुक्रा, पंचाट, सुपुर्दगी, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम, या सम्यक रूप से की गई किसी बात को श्रविधिमान्य नही बनाएंगे; और कोई ऐसी अधिसूचना, आवेश, अनुक्राप्ति, अनुक्रा, पंचाट, सुपुर्दगी, कुर्की, उपविधि, नियम, विनियम या बात उसी रीति में, उसी विस्तार तक और वैसी ही परिस्थितियों में प्रतिसंहत की जा सकेंगी या उसमें फेरफार किया जा सकेंगा या उसे समाप्त किया जा सकेंगा मानों वह इस आदेश के प्रारम्भ होने के पण्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबन्धों के अधीन और के अनुसार बनाई गई थी, जारी की गई थी या की गई थी।

# **प्रनुसू**ची

बेंगाल पब्लिक डिमान्डस रिकवरी एक्ट, 1913

(1913 का बेंगाल एक्ट 3)

वारा 5. — उपधारा (1) में, परन्तुक में, "ग्रसम" के स्थान पर "श्रहणाचल प्रदेश" रखें। ससम वम विनियम, 1891

(1891 का विनियम 7)

घारा 1. - उपधारा (2) में, "असम सरकार द्वारा प्रशासित समस्त राज्यक्षेत्रों" के स्थान पर "समस्त श्रदणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र" रखों।

[सं० फा० 19 (1)/72-एल**० म्राई० वाल० IV**]

के ०के ०सुन्दरम, सचित्र।